(b) if so, what are the targets fixed during the current financial year regarding the major and medium irrigation projects which are being financed by the Central Government, State-wise?

THE MINISTER OF IRRIGATION (SHRI KEDAR PANDEY): (a) Irrigation is a State subject. Funds for execution of major and medium irrigation projects are provided by the State Governments within the frame work of their overall developmental plans. Central assistance to State plans is given in the form of block loans/grants which are not related to any individual sector of development or project.

(b) Does not arise.

कृषि प्रयोजनों के लिए डीजल की खपत

3396. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि प्रयोजनों के लिए डीजल की कितनी खपत होती है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध करने का है कि किसानों को समय पर डीजल की पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध हो; और

(ग) यदि हां, तो यह वितरण प्रणाली कब तक लागू की जायेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 1979–80 के दौरान देश में हाई स्पीड डीजल तेल (एच एस डी) की कुल खपत लगभग 9.33 मि० मी० टन थी । मेरा मंत्रालय अक्तूबर, 1979 से राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों की उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को किसी निर्धारित कोटे के बिना ही हाई स्पीड डीजल का मासिक आवंटन कर रहा है । यह राज्य सरकार के लिए ही है कि वह अपने राज्य के अन्दर के विभिन्न उपभोक्ताओं को डीजल का आगे और आवंटन करें । राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे डीजल के आवंटन के लिए कृषि आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे । इसलिए कृषि प्रयोजनों के लिए डीजल की खपत के आंकड़े मेरे मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार ने आयात करके तटीय स्थलों पर डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं । देश की शोधनशालाओं में उत्पादन को अधिकतम किया गया है और उपलब्ध परिवहन क्षमता का इष्टतम प्रयोग किया जा रहा है । राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को हाई स्पीड डीजल की सप्लाई पहले ही बढ़ाई गई है । राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को परामर्श दिया गया है कि वे कृषि के लिए डीजल की सप्लाई को अधिकतम प्राथमिकता दें ।

Horrowing Experience by Industrial Consumers in Private Sector

3397. SHRI NAVIN RAVANI:
SHRI CHITTA BASU:

Will the Minister of ENERGY AND COAL be pleased to state:

(a) is it true that private sector industrial consumers in coal belt have to go through horrowing experience of paying "speed money" or "hush money" at centres like Government's coal company officials, colliery staff, loaders and local 'dadas' in order to get quality coal in right time from Government-run collieries; and

(b) if so, action taken or planned to curb such illegal activities; do Government propose to institute an enquiry and take concrete steps?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). No specific instance of such harassment has come to the notice of the Government. Any complaint regarding corruption at any level is promptly investigated by the vigilance organisation of the coal companies and necessary action taken against the defaulting personnel. Staff posted in sensitive positions is transferred from one place to another at periodical intervals.

Production of Fertilizers

3398. SHRIMATI KRISHNA SAHI: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether the production of Fertilizer remained static during the years 1977—1979; and